[श्री शीलभद्र याजी]

कतिपय सदस्यों ने सरकार को चेतावनी दी है खाद्य नीति के बारे में और समाजवादी नीति के बारे में। हमारी जो ढुलमुल नीति है उसका परित्याग करना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए हमको खेद के साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रपति ने जो हमारी सरकार की मूल नीति है संसद में बताई हुई नीति है समाजवादी राज बनाने की उसके बारे में जिक्र तक नहीं किया। जब दोनों सदनों के सामने राष्ट्रपति भाषण देते हैं तो सरकार की जो मूल नीति है उसके बारे में उल्लेख भी नहीं करते कि समाजवादी व्यस्था बनाने में समाजवादी राज बनाने में हमारी सरकार क्या करने जा रही है। ठीक है कि इतने बरसों के बाद हम दूसरे देशों से गल्ला नहीं लेंगे मदद नहीं लेंगे लेकिन इसके साथ साथ उनको बताना चाहिए था कि हमारी सरकार समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए ये-ये रास्ते लेगी ये-ये कदम उठाएगी। यह राष्ट्रपति के भाषण में एकदम नहीं है। इसलिये हम सरकार को बताना चाहते हैं हैं कि कांग्रेस सरकार को समाजवाद की स्थापना की नीति अपने सामने रखनी पड़ेगी। इस सदन में और बाहर हम बारबार कहते रहे हैं कि अब ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। सब लोंगो की यह मांग है। जनता की भी मांग हैं वोटर की मांग है कि जल्दी से जल्दी जो इस देश में गरीबी है उस गरीबी का उन्मूलन हो। हो सकता है कि जब समाजवादी व्यवस्था कायम हो तो दल भी सहयोग करें। इसलिए सरकार की जो ढुलमुल नीति है वह समाप्त हो। समाजवाद की जो धीमी रफ्तार है उसको तेज करना पड़ेगा और 1970 तक इस देश में समाजवादी रिपब्लिक बनाने की नीति सरकार को घोषित करनी चाहिए। जो संविधान है कांस्टीट्यूशन है उसमें रेडीकल अमेंडमेंट, संशोधन करने की जरूरत है। जो कल-कारखाने बेसिक इन्डस्ट्रीज हैं बैंक हैं उन सबका जल्दी जल्दी सरकार को राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। जितने गवर्नमेंट मुलाजिम हैं वे सब खिलाफ हो गए कि जैसे भी करो सरकार को गिराओ चूंकि मंहगाई भत्ता नहीं देती। उनकी पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम नहीं करती है। इसलिए यदि ज्यादा से ज्यादा बैंकों का, कारखानों का और बाकी चीजों का समाजीकरण करेगी तो उसके पास इतना धन हो जायेगा कि उसे अमरीका के पास रूस के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा भत्ता देकर खुशकर सकती है। इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी 1970 तक इन्डिया को सोशलिस्ट रिपब्लिक डिक्लेयर करके इन सब चीजों का राष्ट्रीयकरण करने की रफ्तार तेज करनी चाहिए। वोटरों ने जो चेतावनी दी है उसके मुताबिक आप समाजवादी व्यवस्था कायम करिए और आर्थिक दशा सुधारिए। मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं हमारे हिन्दुस्तान की जो 50 करोड़ जनता है जो उनको दुख है तकलीफ है जो गरीबी है बेकारी है उन सब चीजों का समाधान रामबाण औषधि है समाजवादी व्यवस्था। उसके लिए हमारे राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कोई जिक्र नहीं किया। उनको जिक्र करना चाहिए था कि जल्दी से जल्दी समाजवादी व्यवस्था कायम की जाय भले ही स्वतंत्र पार्टी के लोग चिल्लपों मचाते रहें। धीमी रफ्तार से चलने वाली समाजवाद की गाड़ी को तीव्र करना पड़ेगा यही हमारी सरकार से प्रार्थना है।

श्री लोकनाथ मिश्र : लोगों ने आपको वोट नहीं दिया इसलिए समाजवादी ढांचे की बात करते हैं।

श्री शीलभद्र याजी : आपको उठाकर फेंक देंगे।

ALLOCATION OF TIME FOR GOVERNMENT BUSINESS

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting

held today has recommended allocation of time for Government business as follows:

Government Business	Time Allotted	
1. General discussion on the General Budget for the year 1967-68	1 day	(28-3-1967)
2. General discussion on the Railways Budget for the year 1967-68	4 hours	(29-3-1967)
3. General discussion on the Goa, Daman and Diu Budget for the year 1967-68	1 hour	
4. Consideration and return of the Appropriation Bills relating to the following :— (a) Demands on Account (General) for 1967-68. (a) Supplementary Demands for Grants (General) for 1966-67 (c) Demands on Account (Railways) for 1967-68 (d) Supplementary Demands for Grants (Railways) for 1966-67 . . . . (e) Demands on Account (Goa, Daman and Diu) for 1967-68 (f) Supplementary Demands for Grants (Goa, Daman and Diu) for 1966-67	1 day	(30-3-1967)
5. General discussion on the Rajasthan Budget for 1967-68 6. Consideration and return of the Appropriation Bills relating to the following :— (a) Demands on Account (Rajasthan) for 1967-68 (b) Supplementary Demands for Grants (Rajasthan) for 1966-67 7. The Armed Forces (Special Powers) Continuance Bill, 1967	1 day	(30-3-1967)
8. Motion regarding Proclamation issued under article 356 of the Constitution in relation to the State of Rajasthan	1 day	(3-4-1967)
9. Short duration discussion under Rule 176 regarding disclosures contained in the Book "The Untold Story" by Lt. General B. M. Kaul	2 hours	

In order to be able to complete the •business, the Committee further re- •comsmended that the House might curtail or dispense with the lunch recess and sit up to 6.00 P.M. on all the days up to the 31st March, 1967.

3 P.M.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENTS ADDRESS—*contd.*

SHRI M. N. KAUL __ (Nominated): Madam Deputy Chairman, I should like to make a few suggestions arising out of the crisis in Rajasthan. I have had the advantage of listening to the debates in this House and also of following the debates in the other House. There have been many speeches, but the facts lie within a narrow compass. The election results were completed on 25th February. The Assembly was dissolved on the / 28th February. So, it was open to the Governor on the 1st of March to summon the leader of the Congress Party, which was the largest single Party in the Assembly to form a Government. If he had done so, that would have been in accordance with constitutional practice. The Congress Party did not have a clear majority, but it was the largest single Party, The Governor would have been perfectly in order *to* ask **Mr.* Sukhadfa to form the Government, but he adopted the alternative course, which had also the sanction of constitutional precedents. In England when no Party has a clear majority in the House of Commons, the King must then use his own judgment as to which leader he would summon, subject only to the condition that the person summoned must be able to command a majority by some coalition or comoromise with the other Parties. So, the Governor met